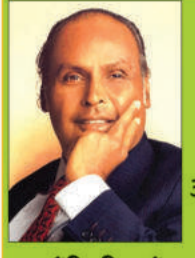


माही की गुंज

www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com



बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे की सोचो

व्यक्ति विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है! धीरुभाई अम्बानी

वर्ष-05, अंक - 22

(साप्ताहिक)

खवासा, गुरुवार 02 मार्च 2023

पृष्ठ-8, मूल्य-5 रुपए

शिवगंगा के हलमा आयोजन का शिवराज सरकार और जिला प्रशासन ने मिलकर बनाया हलवा

सरकार की फूलती दिख रही सांसे, शिवराज ने गिरती साख को बचाने के लिए लिया शिवगंगा का सहारा...

माही की गुंज, संजय भटेवर

झाबुआ। जिले के आदिवासी समाज की एक ऐसी परंपरा जो समाज को एकजुट रखने और एकता के धगे में समाहित होने का संदेश देती रही है। समाज के गरीब और पिछड़े लोगों को हाथ से हाथ मिलाकर उनका सहयोग कर मुख्य धारा से जोड़ने का काम करती रही है। चाहे जिस तरह की विपत्ती हो, यह परंपरा इस आदिवासी समाज को उससे उभरने में मदद करती रही है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इसका अपना अलग ही महत्व है। अपनों से अपनों की मदद करने वाली इस परंपरा का नाम ही हलमा है। गांव के किसी भी गरीब आदिवासी के मुसीबत में पड़ने पर सारे गांव के लोग मिलकर उसकी मदद कर उसे मुसीबत से बाहर निकालते हैं। यह परंपरा यहां यूं तो सदियों से चली आ रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिले का एक संस्था ने इसे सार्वजनिक पटल पर लाकर प्रदर्शित ही नहीं देश भर में पहुंचा दिया।

जिले की शिवगंगा संस्था ने जिस तरह आदिवासियों की इस परंपरा को सार्वजनिक व बड़े कामों के लिए उपयोग किया है, वह सराहनीय है। जिले में इस संस्था ने हलमा के जरिए कई बड़े कामों को अंजाम दिया है। संस्था का एक अपना ही संजाल है जो जिले भर में फैला हुआ है। जब भी आवश्यकता पड़ती यह सड़क बड़े से बड़े कामों को अंजाम दे देता। शिवगंगा जिले में अब तक इसी तरह हलमा कर सैकड़ों तालाबों का निर्माण कर चुका है, तो जिले के कई क्षेत्रों में पौधा रोपण कर उन्हे वृक्षों में तबदील कर जंगल का रूप दे चुका है। हर साल शिवगंगा आदिवासियों की इसी परंपरा का इस्तेमाल कर हलमा का आयोजन करती आ रही है। शिवगंगा द्वारा आयोजित हलम में जिले के सैकड़ों आदिवासी शिरकत करते और जलसंरक्षण को लेकर पहलियों पर कंडूर कर का निर्माण करते। इस कंडूर निर्माण का उद्देश्य यह होता कि, वर्षा जल को संरक्षित कर भू-जल स्तर को बढ़ाया जाए। शिवगंगा का यह उद्देश्य वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन पिछले कई सालों में जिले में कितना भू-जल स्तर बढ़ा है इसका कोई पुख्ता आंकड़ा न तो शिवगंगा के पास है और न ही प्रशासन के पास...? उद्देश्य अच्छा है इसीलिए शिवगंगा के इस अभियान को समर्थन भी मिलता है और इसी जन समर्थन के चलते इस बार इसका पूरी तरह से राजनीतिकरण हो गया।

इस बार 25 और 26 फरवरी को आयोजित हुआ शिवगंगा का यह हलमा पूरी तरह से राजनीतिक भी भेंट चढ़ गया। शिवगंगा के इस आयोजन का सीधे तौर पर शिवराज सरकार ने फायदा उठाने की कोशिश की है। शिवगंगा के इस हलम की तारीखें सामने आने के बाद शिवराज सरकार व जिला प्रशासन ने मानों इस आयोजन का अपहरण कर लिया। 5 से 25 फरवरी तक प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में विकास यात्रा निकालने का ऐलान किया था। यह विकास यात्रा टेड ग्रामीण स्तर तक निकाली भी गई। मगर विकास यात्रा को जनता का कोई खास समर्थन मिलता दिखाई नहीं दिया। विकास यात्रा का पल्लोता होते देख सरकार और जिला प्रशासन ने इसके समापन को सफल बनाने के लिए शिवगंगा के हलमा



भोपाल से लाई गेती के साथ हेलीकाप्टर से उतरे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान।



महज कुछ ही फावड़े चलाकर श्रमदान की कर ली इतिथी।



पहाड़ी पर खड़े रहकर लिया नजारे का आनंद और करवाया फोटो रोशन।

आयोजन पर दाव खेला। क्योंकि शिवगंगा के इस हलमा आयोजन में हजारों आदिवासियों की भीड़ जुटने वाली थी और इसी भीड़ का फायदा शिवराज सरकार और जिला प्रशासन उठाना चाहते थे। बस फिर क्या था शिवगंगा का हलमा आयोजन विकास यात्रा के समापन आयोजन में बदल गया। कहने को तो हलमा कार्यक्रम में विकास यात्रा समापन आयोजन समाहित किया गया था, लेकिन धीरे-धीरे हलमा कार्यक्रम दर किनार रह गया और विकास यात्रा समापन आयोजन ही मुख्य रूप से दिखाई पड़ा।

इस सारे घटनाक्रम से एक बात तो साफ नजर आ रही है कि, प्रदेश भर में विकास यात्रा निकालकर शिवराजसिंह चौहान ने अपनी खिसकती जमीन देख ली है। प्रदेश भर में विकास यात्रा के क्या हाल रहे यह तो नहीं कह सकते लेकिन जिले में विकास यात्रा की जमीनी हकीकत बहुत ही खराब नजर आई है। जिले में विकास यात्रा से आमजन लगभग नदारद ही नजर आया है। भाजपा से जुड़े लोग जरूर इसमें नजर आए, लेकिन कई जगहों पर तो यह भी नहीं देखे गए। स्कूली बच्चों को विकास यात्रा में शामिल कर यात्रा की इतिथी कर ली गई। तो कई जगहों पर अफसर शाही तंत्र ने विकास यात्रा को पल्लोता लगाया।

शिवगंगा के इस हलम में पहले दिन मध्यप्रदेश

के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने शिरकत की और आदिवासियों की इस परंपरा को करीब से जाना। मगर आम आदिवासी जो इस हलमा आयोजन में पहुंचा था, प्रोटोकाल की वजह से उन तक पहुंच भी नहीं पाया। राज्यपाल पूरी तरह से भाजपा नेताओं से ही घिरे रहे। राज्यपाल ने हलमा के बारे में जो भी जाना इन्हीं भाजपा नेताओं और शिवगंगा प्रमुख महेश शर्मा से ही जाना। राज्यपाल ने 25 फरवरी शाम को यहां पहुंचकर गेती यात्रा में हिस्सा लिया। दूसरे दिन उन्होंने आदिवासियों की हलमा परंपरा में हिस्सा लेकर कंडूर खोदने के लिए गेती चलाई। जिसके बाद राज्यपाल यहां से रवाना हो गए।

इसी दिन 26 फरवरी को सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान हलमा आयोजन और विकास यात्रा समापन समारोह में हिस्सा लेने झाबुआ पहुंचे। झाबुआ में हलमा आयोजन में कदम रखते ही शिवराज का अंदाज कुछ ऐसा था कि, वे हेलीकाप्टर से ही गेती हाथ में लेकर उतरे। भाजपा से जुड़े लोग जरूर इसमें नजर आए, क्योंकि गेती तो यहां भी मिल सकती थी, भोपाल से लेकर आने की क्या जरूरत थी? और अगर ऐसा ही था तो फिर फावड़ा और तगारी भी साथ में ही ले आते। या फिर कहीं न कहीं प्रशासन मुख्यमंत्री के लिए गेती तक का इंतजाम नहीं कर पाया। खैर जो भी हो लेकिन शिवराज की एंटी ने

यह तो बता ही दिया कि, यह चुनावी साल है और यह आयोजन उसी को साधने की राजनीतिक नीटकरी रही। हलमा में शिरकत करने के नाम पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महज कुछ ही गेती जमीन पर चलाई। उनके इस श्रमदान से शायद एक भी कंडूर जमीन पर नहीं बना होगा। बस यह हलमा आयोजन का समापन हो चुका था। इसके बाद जो था वह सिर्फ विकास यात्रा का समापन ही था।

मंच से सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने हलमा को महज कुछ शब्दों में निपटारा और विकास यात्रा की ओर पूरे कार्यक्रम को घुमा दिया। हलमा में आई भीड़ अब एक राजनीतिक सभा का हिस्सा बन चुकी थी। जिले में विकास यात्रा की तो इतनी फजीहत हुई थी कि 11 लाख की आबादी वाले इस जिले से विकास यात्रा के समापन के नाम पर भीड़ एकत्रित करना शिवराज और जिला प्रशासन को नामुमकिन सा लग रहा था। जो आंकड़ा प्रशासन भीड़ का बता रहा है वह तीन राज्यों को मिलाकर बता रहा है। मतलब साफ है कि, हलमा आयोजन के नाम पर या विकास यात्रा के समापन के लिए जो भीड़ इकट्ठी की गई थी उसमें जिले के ग्रामीणों की संख्या कितनी रही होगी। हालांकि प्रशासन द्वारा भीड़ के लिए आंकड़े और जमीनी हकीकत में जमीन-आसमान का फर्क बहुत आसानी से दिखाई पड़ता

है। जिस भीड़ को जिला प्रशासन 40 हजार बता रहा है, वह हकीकत में लगभग उससे आधी या उससे भी कम होगी। क्योंकि जिले की जनता ने कई बार हजारों-लाखों की भीड़ देखी है। आने वाले भगोरियों में भी इससे ज्यादा भीड़ देखने को मिल जाएगा।

सवाल तो यह भी है कि क्या शिवराज सरकार और जिला प्रशासन ने जिले में इतने भी काम नहीं किए कि लगभग 11 लाख की आबादी वाले इस जिले से विकास यात्रा के समापन अवसर पर 1 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा कर सके। विकास यात्रा के नाम पर यह जरूर हुआ है कि, जो लोग बरसों से अपनी समस्या को लेकर दौड़ रहे थे, उन्हें विकास यात्रा के ढकोसले में सफलता मिल गई। ऐसे कई उदाहरण जिले में भरे पड़े हैं जो बरसों से प्रशासनिक निकर्मण का शिकार हो रहे थे, दर-दर की टोकरे खा रहे थे, लेकिन चुनावी साल और मामा को दिखती खिसकती जमीन ने विकास यात्रा के नाम पर किए गए ढकोसले में उनकी सुन ली और समस्या का समाधान हो गया। 2003 के बाद कुछ महीनों को छोड़ शिवराज की सरकार है। बावजूद इसके अब भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें या तो योजनाओं का लाभ नहीं मिला या वे किसी न किसी तरह से प्रशासनिक हटधर्मिता के शिकार हुए हैं। अब जब कि चुनावी साल है और शिवराज सरकार को अपनी जमीन जाती दिखाई पड़ रही है

तो शिवराज ने विकास यात्रा निकाल कर महज 20 दिनों में सारे विकास कर डाले। लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान कर डाला। विकास यात्रा के समापन समारोह में प्रशासन ने जिस तरह से आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। उससे तो यही साबित होता है कि, विकास यात्रा के 20 दिनों के पहले विकास हुआ ही नहीं था, जो कुछ भी हुआ है वह महज इन 20 दिनों में ही हुआ है।

हनुआ करोड़ों का खर्च

सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि, शिवगंगा हलमे के जिस आयोजन को अल्प खर्च में करती थी, उसी आयोजन पर इस बार प्रशासन ने करोड़ों रुपये खर्च कर डाले। सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह खर्च 6 करोड़ से भी अधिक है। हालांकि अगर यह खर्च वाकई में शिवगंगा द्वारा चलाए जा रहे हलमा आयोजन के लिए होता तो शायद इस जिले की तस्वीर ही बदल गई होती। मगर अफसोस इस बात का है कि, सरकार और प्रशासन ने यह पैसा हलमा पर नहीं बल्कि विकास यात्रा के समापन और शिवराज सरकार की खिसकती जमीन को सहाय देने के लिए किया। शिवगंगा हलमा का आयोजन पिछले कई वर्षों से करती आ रही है, और आयोजन का खर्च भी बहुत कम होता है, लेकिन यह पहला मौका है जब उसके आयोजन में घालमेल कर प्रशासन ने करोड़ों रुपये

फूंक दिए और नतीजा सिफर ही रहा। इस बार सरकार और प्रशासन की दखल अंदाजी से हलमा का असल मकसद शायद दूर ही रह गया और आयोजन का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो गया। इस मामले में कांश्रिस भी हलमा के राजनीतिकरण को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी है।

कुल मिलाकर इस बार शिवगंगा के हलमा आयोजन का शिवराज सरकार और जिला प्रशासन ने मिलकर हलवा बना दिया। हलमा को एक तरह का विकास यात्रा का समापन कराया। अब यह हलवा सरकार का कितना मुंह मीठा करेगा यह तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन एक बात तो साफ हो चली है कि, सरकार को विकास यात्रा करने पर अपनी जमीन खिसकती नजर आ गई है। विकास यात्रा में मुंह की खाने के बाद 'अंत भला तो सब भला' तर्ज पर उसके समापन अवसर को धुनाने के लिए शिवगंगा के हलमा का हलवा बनाया गया।



करोड़ों रुपये खर्च कर हलमा उर्फ विकास यात्रा समापन की सभा को संबोधित करते मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान।



हलमा करने पहुंचे ग्रामीण बन गए राजनीतिक सभा का हिस्सा।

बजट से पहले विपक्ष ने गैस सिलेंडर को लेकर किया विरोध प्रदर्शन

भोपाल।

वैसे तो यह साल मध्य प्रदेश के लिए काफी अहम है क्योंकि इसी साल यहां विधानसभा चुनाव होने हैं। बुधवार को दिन एमपी के लिए इसलिए भी खास रहा क्योंकि इस दिन सरकार ने अपना बजट पेश किया। राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जब विधानसभा में बजट पेश करने पहुंचे थे तब उससे पहले कांश्रिस विधायकों ने महंगाई के विरोध में विधानसभा के बाहर सिलेंडर के साथ प्रदर्शन भी किया। विधायक सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध कर रहे थे। वित्त मंत्री ने जब विधानसभा के अंदर अपना बजट पेश किया तब उस वक भी काफी शोर-शराबा हुआ। सदन में मौजूद विधायक ने जय महाकाल और जय श्रीराम के नारे भी लगाए।

राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इस लिहाज से शिवराज सरकार का यह बजट काफी अहम माना जा रहा था। इस बजट में वित्त मंत्री ने महिला सशक्तिकरण की बात कही। प्रदेश के पहले ई-बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत राज्य

हंगामे के बीच वित्त मंत्री देवड़ा ने पेश किया चुनावी बजट...!

की 44 लाख से अधिक छात्राओं के तहत 44 लाख से अधिक छात्राओं को लाभ मिला है। इस बजट में किसी भी नये टैक्स का ऐलान नहीं किया गया था।



बजट भाषण के दौरान जब विपक्ष बार-बार हंगामा कर रहा था तब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला और कहा कि, जनता इस बजट को सुनना चाहती है लिहाज जा विपक्ष भाषण के दौरान शोर ना मचाए और बाद में अपनी बातें रखे। इस बजट में उच्च शिक्षा में दाखिला लेने वाली बालिकाओं को ई-स्कूटी देने का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने बताया कि मातृत्व वंदना योजना के तहत 467 करोड़ रुपये दिए जाने वाले हैं। वहीं महिला स्वयं सहायता समूह को 660 करोड़ मिलेंगे। वित्त मंत्री इसके साथ ही कहा सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दे रही है।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि, प्रसूति सहायता योजना के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 11 हजार एकड़ में सुगंधित खेती को बढ़ावा देने के अलावा स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात बजट में कही गई है। खेल विभाग के लिए 738 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया गया है। किसानों के लिए शिवराज सरकार ने एक अहम बात यह भी कही है कि डिफॉल्टर हो चुके किसानों का कर्ज अब सरकार भरेगी।

शराब ठेकेदार के पक्ष में नीति बनाने वाली सरकार, उमा को संतुष्ट करने के लिए अहाते बंद करने का ठ्कोसला

गांव-गांव में बिक रही अवैध शराब पर शिवराज को कोई एतराज नहीं लेकिन शराब पीकर वाहन चलाने वाले के होंगे लाइसेंस निरस्त

माही की गूँज, झाबुआ।
मुज्जमिल मंसुरी

2003 में भाजपा की उमा भारतीय सरकार ने बड़े शराब ठेकेदारों की मोनोपॉली खत्म करते हुए एकल शराब दुकान प्रणाली लागू की गई, जिसमें सरकार का ध्येय यही था कि, बड़े शराब ठेकेदार अपनी मोनोपॉली चलाकर बड़े रूप से शराब ठेके की आड़ में अवैध शराब बिक्री का कार्य किया जाता है। वहीं एकल प्रणाली के साथ बड़े ठेकेदारों की मोनोपॉली खत्म होने के साथ ही जिले व गांव स्तर के उन लोगों को भी लाभ मिलेगा जो स्थानीय स्तर पर अवैध शराब बेचते हैं। वे इस ठेके पद्धति से एक-एक दुकान लेकर अपना व्यवसाय बिना किसी मोनोपॉली के साथ सीधे सरकार द्वारा आबकारी नीति के तहत ड्यूटी वाली ही शराब बेची जाएगी। जिससे सरकार को प्रदेश में बिकने वाली शराब का पूरी मात्रा में राजस्व मिलेगा साथ ही अवैध शराब बिक्री पर अंकुश होकर कई लोगों को इस नीति से जोड़ने का प्रयास किया गया था। और छोटे लोगों में उत्साह होकर शराब व्यवसाय से जुड़े छोटे लोगों ने उमा भारती की शराब नीति से खुश हुए नतीजन अपने भाग्य आजमाकर लाटरी पद्धति से शराब दुकानें भी आवंटित हुईं। जिससे बड़े ठेकेदारों की मोनोपॉली पूरी तरह खत्म हो चुकी थी लेकिन शिवराज सरकार ने बड़े ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने व छोटे ठेकेदार को धीरे-धीरे दरकिनार हो जाए की पॉलिसी बनाई। एकल प्रणाली की शराब नीति को गुप प्रणाली यानी की एक से अधिक दुकान बड़े ठेकेदारों अनुसार दो से लेकर चार से पांच दुकानों का गुप बनाकर नीति में फेर बदल कर दुकानें दी गईं।

इतना प्रभावित हो गया कि आने वाले 2023-24 के चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों को लेकर भी इनकी सहमती सर्वमान्य मानी जावेगी की स्थिति में है।

2022-23 में भी कमपोजिट दुकान के साथ ठेकेदारों को पहुंचाया बड़ा लाभ

कहने को तो मध्यप्रदेश में 3608 दुकान शराब की है और शराब दुकान से शराब लेकर बैठक व्यवस्था के रूप में शराब पीने हेतु आहते 2611 थे। 3608 कुल शराब दुकानों में देशी व विदेशी की प्रथक-प्रथक शराब दुकानें थी, लेकिन शिवराज सरकार ने एक बड़ा लाभ शराब ठेकेदारों को पहुंचाने के लिए 2022-23 नीति के तहत कमपोजिट दुकान की नीति लागू करने के साथ ही देशी शराब पर विदेशी व विदेशी पर देशी शराब बेचने की व्यवस्था कर सीधे रूप से दो गुना दुकानें करने का कार्य किया है।

इस नीति के साथ सरकार ने भले ही टीपी परमिट को 2022-23 की नीति में बंद किया गया था। जिसमें एक शराब दुकान से दूसरी शराब दुकान पर शराब लाने लेजाने में यह टेम्पेरी परमिट था। लेकिन शराब ठेकेदारों को एक शराब दुकान से दूसरी शराब दुकान पर शराब लाने लेजाने के नाम पर अवैध शराब बेचने में टीपी परमिट बंद होते ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। नतीजन शराब ठेकेदारों के पक्ष में पुनः कुछ ही दिनों में एक कैबिनेट बैठक के साथ शराब ठेकेदारों को अवैध रूप से शराब सप्लाय करने का माध्यम टीपी परमिट को पुनः पूर्व की तरह लागू कर दिया गया।

2023-24 की नई आबकारी नीति के तहत सरकार ने उमा भारती के विरोध के बाद शराब दुकानों के पास सिटी में संचालित होने वाले 2611 आहते को बंद करने की नीति बनाई। साथ ही कोई वाहन चालक शराब पीकर वाहन चलाता है तो उसके लाइसेंस निरस्त करने की नीति भी बनाई। शिवराज की यह नीति महज ही उमा भारती को संतुष्ट करने के लिए ही बनाई गई है यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि शिवराज सरकार 2023 में अपनी चुनावी बाजी जीतने के लिए फिलहाल सभी रूठों को संतुष्ट करने की नीति अपनाकर 2023 के चुनाव में अपनी बाजी जिताना चाहते हैं। लेकिन शिवराज कि यह दोगली नीति कहां तक सार्थक होगी यह तो चुनाव व चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हकीकत तो यह है कि, शिवराज चौहान की सरकार में शराब माफियां बेखोफ है और आहते तो प्रदेश में आबकारी रिकॉर्ड अनुसार 2611 थे लेकिन असल में सर्व सुविधा के साथ अवैध रूप से शराब के अंडे जहां बैठकर शराब पिलाई जाने वाले अंडे उर्फ आहते एक-एक जिले में ही 2611-2611 से भी अधिक है।

आदिवासी बाहुल्य जिला झाबुआ व अलीराजपुर की ही बात करें तो दोनों जिले गुजरात से सटे होकर दोनों जिलों में गांव-गांव में अवैध शराब दुकानें होकर दिनदहाड़े हो या रात के अधियारे चौबीसों घंटे खुलेआम शराब ठेकेदार गोदामों से अवैध रूप से शराब भरकर वाहनों से शराब ढोई जाती है। वहीं गांव-गांव में शराब के अवैध अहाते होकर मंदिर हो या स्कूल या मुक्तिधाम हो या कब्रिस्तान के साथ ही पुलिस चौकी या थाने के समीप ही 100 से 500 मीटर के दायरे में ही बड़े पैमाने पर अवैध शराब बिक रही है। इतना ही नहीं इन दोनों जिलों में जितनी शराब अवैध रूप से गांव-गांव में ढोई जाती है उतनी ही शराब प्रतिदिन यहां की शराब दुकानों से गुजरात में ढोई जाती है। शिवराज सरकार ने 2611 अहाते बंद कर व शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक पर सख्त कार्रवाई करने की नीति बनाई है, लेकिन सरकार की पॉलिसी में अवैध शराब बेचने वाले ठेकेदार का लाइसेंस निरस्त नहीं किया जाता है और ठेकेदार गांव-गांव में शराब पहुंचा रहे हैं



सिर्फ एक दूरक-रामपुर शराब दुकान के गोडउन से क्षेत्र में कई वाहनों से शराब का परिवहन होकर गांव-गांव में ढोई जाती है।



जिस पर कोई प्रतिबंध या सख्त कार्यवाही की नीति नहीं बनाई जा रही है। इसी के बिच शिवराज सिंह चौहान आदिवासी के वोट बैंक को लुभाने के लिए पलायन रही विकास यात्रा के समापन में हलमा आयोजन को विस्तार रूप देने के साथ अपनी कमियों को दबाने का प्रयास किया है। देखते है माफियाओ के बीज को विकराल करने वाले शिव की गंगा 2023 में कंहा बहती है।

देश का पहला साइलेंट स्टेशन बना चेन्नई सेंट्रल



चेन्नई, एजेंसी। रेलवे स्टेशन पर पहचाने के बाद सबसे पहले आपको सुनाई देती है तो वह है ट्रेनों की आवाजाही से संबंधित अनाउंसमेंट। यात्रीगण कृपया ध्यान दें! यह वाक्य रेलवे स्टेशन की निशानी बन चुका है। हालांकि अब चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन साइलेंट स्टेशन बन गया है।

डॉ. एमजीआर रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन ने ऑडियो अनाउंसमेंट बंद करने का फैसला किया है। यह देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है। अब इस स्टेशन पर विजुअल डिस्प्ले और इन्कायरी बुथ के जरिए ही ट्रेनों की जानकारी मिल सकेगी। शनिवार को साउथ रेलवे जनरल मैनेजर आरएन ने इस फैसले का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि सभी डिस्प्ले बोर्ड ठीक तरीके से काम कर रहे हों। इसके अलावा पूछताछ खिड़कियों पर पर्याप्त स्टाफ को भी बैठाया गया है। तीनों एंटी पॉइंट्स पर भी डिजिटल स्क्रीन लगाई गई हैं।

इन स्क्रीनों पर तीन भाषाओं में ट्रेनों की आवाजाही की जानकारी दी जाएगी। तमिल, अंग्रेजी और हिंदी में सूचना दिखाई देगी। आसपास के इलाकों में भी तीन डिजिटल बोर्ड लगाए गए हैं। हालांकि सबअर्बन ट्रेनों के लिए अनाउंसमेंट जारी रहेगा। इस बारे में लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ऐलान से जानकारी जुटाने में आसानी रहती थी। वहीं कई लोगों का कहना है कि इससे अनापड़ लोगों को दिक्रत का सामना करना पड़ेगा। दिव्यांगों के लिए ब्रेल नैविगेशन मैप भी लगाए गए हैं।

चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन करीब डेढ़ सौ वर्ष पुराना है। इस स्टेशन पर पहली बार इस तरह की पहल की गई है। अब यात्रियों और कर्मचारियों की प्रतिक्रिया ली जाएगी और इसके बाद ही फैसला किया जाएगा कि यह सिस्टम कारगर है या नहीं।

राज्य में बनेंगे 3 हजार मंदिर, एक-एक मंदिर पर खर्च होंगे 10 लाख रुपए

अमरावती, एजेंसी।

हिंदू आस्था की रक्षा के नाम पर आंध्र प्रदेश की जगन मोहन सरकार ने राज्य में 3 हजार हिंदू मंदिर बनवाने का फैसला लिया है। राज्य सरकार का कहना है कि, पूरे प्रांत में मंदिरों के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। तीर्थों को विकसित किया जा रहा है। राज्य के डिप्टी सीएम कोड्डू सत्यनारायण ने कहा कि सीएम रेड्डी ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि हिंदू आस्था का संरक्षण और प्रचार किया जा सके। सत्यनारायण ने कहा, हिंदू आस्था का बड़े स्तर पर प्रचार करने के लिए सरकार ने कमजोर तबके

के लोगों के इलाकों में मंदिरों के निर्माण का फैसला किया है। मंदिरों के निर्माण के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के श्री वाणी ट्रस्ट की ओर से हर मंदिर के निर्माण के लिए 10 लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी। पहले राज्य में एक हजार 330 मंदिरों के निर्माण का फैसला लिया गया था। अब इस लिस्ट में एक हजार 465 मंदिर और जोड़े गए हैं। इसके अलावा कुछ विधायकों की मांग के आधार पर 200 और मंदिर बनाए जाएंगे। बचे हुए मंदिरों का निर्माण स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि फिलहाल पूरे प्रदेश में 978 मंदिरों को बनाने पर काम तेजी से चल रहा है।

उन्होंने कहा कि, 25 मंदिरों के निर्माण के लिए एक इंजीनियर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री ने कहा कि 270 करोड़ रुपए का बजट आवंटन मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए जारी किया गया है। यही नहीं मंदिरों में तमाम धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भी 238 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यही नहीं धूप, दीप के लिए भी 28 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। इस तरह यह रकम हर मंदिर के हिस्से में 5 हजार रुपए आएगी। जगन मोहन रेड्डी सरकार ने धूप, दीप स्कीम के तहत 2019 में सिर्फ एक हजार 561 मंदिरों को ही शामिल किया गया था। अब इनकी 5 हजार तक पहुंच गई है।

समूह को अनाज वितरण की सोसायटी दिलवाने के नाम पर सचिव ने लिए दस हजार, कैमरे में हुआ कैद



पंचायत में ही मिलीभगत कर शुरू कर दी सोसायटी, एसडीएम को आवेदन देकर कार्यवाही की मांग

माही की गूँज, पेटलावद।
राकेश गोहलोत

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चाहे मंच पर कितने ही दावे कर ले की भ्रष्टाचार और रिश्वत पर लगाम लगा रखी है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बया करती है और सरकार के नुमाइंदा खल कर रिश्वत लेकर सरकार की भ्रष्टी पलीत कर रहे हैं, ये रिश्वतखोर कर्मचारी कैमरे में कैद होने के बाद भी अपने अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त कर बच जाते हैं, विगत दिनों रतलाम जिले के जावरा विकास खण्ड में एक पटवारी रिश्वत लेता कैद हुआ था। अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त ये पटवारी बच ही गया था कि, खबर

मीडिया में प्रकाशित होकर मामला उजागर हो गया जब कही जाकर फंस रहे अधिकारी ने अपनी गर्दन बचाते हुए पटवारी को निर्लंबित कर दिया, ऐसा ही एक मामला अब पेटलावद विकास खण्ड में आया है जहां ग्राम पंचायत का सचिव समूह गाँव में सोसाईटी खुलवाने के नाम पर दस हजार की रिश्वत लेता है और कैमरे में कैद हो जाता है। मामले की शिकायत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास की गई है फिलहाल सचिव पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है शायद यहां भी जिम्मेदार मामला सुलटाने की फिराक में है या मीडिया में आने का इंतजार कर रहे हैं जिसके बाद शायद रिश्वतखोर सचिव पर कोई कार्यवाही हो।

समूह को सोसायटी दिलवाने के नाम पर ली राशि, कैमरे में हुआ कैद मंत्री

पेटलावद विकास खण्ड के ग्राम पनास ग्राम पंचायत काजबीगोबरिया गरवाल ने बताया कि, वो सागर स्वयं सहायता समूह का संचालन करते हैं और मेरी पॉलिन अगुरीबाई उक्त समूह कि सचिव है और पनास के ग्रामीणों के द्वारा सोसाईटी से अनाज लेने के लिए रायपुरिया आना पड़ता था, शासन द्वारा सोसाईटी के संचालन का कार्य समूह के द्वारा करवाए जाने की योजना अन्तर्गत ग्राम पनास मे सोसाईटी स्वीकृत हुई जिसका आवेदन उक्त

समूह के माध्यम से किया जाना था, जिसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव-उहराव समूह के पक्ष में कर दिया गया था। सोसाईटी स्वीकृत करवाने हेतु आवेदन के लिए आनलाईन पोर्टल नहीं खुलने के कारण आवेदन नहीं हो पाया, जिसकी जानकारी लेने हेतु ग्राम पंचायत काजबी के सचिव दयाराम गवली से सम्पर्क किया गया, तो उसके द्वारा प्रार्थी को सोसाईटी स्वीकृत करवाने की जवाबदारी लेते हुए प्रार्थी से बीस हजार रूपए की मांग की जिसमें से दस हजार रूपए ग्राम पंचायत भवन पर मौजूद सचिव दयाराम गवली को दिए गए। सचिव पर भरोसा नहीं होने के कारण आवेदक ने सचिव को पैसे देते हुए विडियो बना लिया।

समूह की सोसायटी नहीं हुई, ग्राम पंचायत से शुरू हो गया अनाज वितरण

काफ़ी समय बीत जाने के बाद ग्राम पंचायत भवन पर ही सोसाईटी शुरू होकर ग्राम पंचायत के माध्यम से अनाज वितरण का कार्य रायपुरिया सोसाईटी से सेल्समेन भेज कर करवाना शुरू कर दिया। जिसकी जानकारी मिलने पर आवेदक गोबरिया गरवाल द्वारा सचिव दयाराम गवली से मेरे समूह की सोसाईटी स्वीकृत नहीं होने का कारण पूछ तो इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया और दिए गए पैसे वापस मांगें तो पैसे वापस नहीं दिए।

मिलीभगत से शुरू की सोसायटी

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि, ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक तीनों मिलकर अनाज वितरण करने वाले सेल्समेन के साथ मिलकर ग्रामीणों को मिलने वाले अनाज की कालाबाजारी के उद्देश्य से उक्त सोसाईटी शासन के नियमानुसार किसी स्थानीय समूह के लिए जाने के बजाए स्वयं ग्राम पंचायत से अनाज वितरण का कार्य शुरू कर दिया जो जांच का विषय है। गोबरिया गरवाल ने सचिव दयाराम गवली पर कार्यवाही की मांग करते हुए एसडीएम को आवेदन दिया है।